

सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस (SoO) संधिक्रिया है?

- कुकी के साथ SoO समझौते पर वर्ष 2008 में भारत सरकार और मणपुरि व नगालैंड के पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय विभिन्न कुकी आतंकवादी समूहों के बीच युद्धविराम समझौते के रूप में हस्ताक्षर किये गए थे।
- समझौते के तहत कुकी आतंकवादी समूह हसिक गतिविधियों को बंद करने और नगिरानी के लिये नरिदषिट शक्ति में सुरक्षा बलों के आने पर सहमत हुए।
- इसके बदले में भारत सरकार कुकी समूहों के खिलाफ अपने अभियान को नलिंबति करने पर सहमत हुई।
- संयुक्त नगिरानी समूह (JMG) समझौते के प्रभावी कार्यान्वयन की देख-रेख करता है।
- राज्य और केंद्रीय बलों सहित सुरक्षा बल व भूमिगत समूह अभियान शुरू नहीं कर सकते।

वदिरोही समूहों से नपिटने के लिये प्रशासनिक व्यवस्थाएँ क्या हैं?

- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (DoNER):
 - यह क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिये पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास योजनाओं और परियोजनाओं की योजना, कार्यान्वयन और नगिरानी से संबंधित मामलों के लिये ज़िम्मेदार है।
- इनर लाइन परमिट (ILP):
 - मज़ोरम, नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश के स्वदेशी लोगों की मूल पहचान बनाए रखने के लिये बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है, इनर लाइन परमिट (ILP) के बिना बाहरी लोगों के प्रवेश की अनुमति नहीं है।
- संवैधानिक प्रावधान:
 - इन प्रावधानों के अनुसरण में कारबी आंगलॉग, खासी पहाड़ी ज़िले, चकमा ज़िले आदि जैसे विभिन्न जातीय समूहों की मांगों को पूरा करने के लिये विभिन्न स्वायत्त ज़िले बनाए गए हैं।
 - अनुच्छेद 244 (1) में प्रावधान है कि 5वीं अनुसूची के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन या नयित्रण पर लागू होंगे।
 - अनुच्छेद 244 (2) में प्रावधान है कि 6वीं अनुसूची के प्रावधान इन राज्यों में स्वायत्त ज़िला परिषद बनाने के लिये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मज़ोरम राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन या नयित्रण पर लागू होंगे।

नषिकर्ष:

मणपुरि के साथ वृहद पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति लाने के लिये केंद्र और मणपुरि की सरकारों एवं UNLF के मध्य शांति समझौता आवश्यक है। ऐतिहासिक समझौता UNLF को मुख्यधारा में वापस लाकर लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों के समाधान की दशा में अग्रसर है। जबकि अन्य वदिरोही समूहों के साथ तुलनीय समझौते क्षेत्रीय मुद्दों को हल करने और विकास को बढ़ावा देने के लिये नरितर प्रयासों का संकेत देते हैं, शांति नगिरानी समिति ज़मीनी मानदंडों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिये बाहरी राज्य और गैर-राज्य अभिनिताओं द्वारा उत्पन्न बहुआयामी चुनौतियों का वश्लेषण करें, साथ ही इन खतरों से नपिटने के लिये उठाए जाने वाले आवश्यक उपायों पर भी चर्चा कीजिये। (2021)